Shri Raj Bahadur: No such uggestion has been made. In fact, certain press reports appeared, but they essentially concentrated attention of the readers on the need for increase of tolls and levies for the maintenance of navigational facilities, like conservancy and other facilities, on the East Pakistan river system.

Shri Basumatari: In view of the unholy and unfriendly attitude of Pakistan—they might create difficulties in river navigation—may I know what precautionary measure has been taken by Government for transhipment from Jogighopa to other parts of Assam?

Shri Raj Bahadur: We are trying to re-organise the road transport. In this connection we have also set up a Government road transport organisation for transport of goods from Calcutta to Assam and we hope that in any time of stress or strain or emergency we might fall back upon these two systems, that is, rail and road transport.

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इससे हमारे भारत को कितने परसेंट का लाभ होगा और उस को मेक-अप करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री राज बहादुर: वहां पर लास का सवाल ही पदा नहीं होता है क्योंकि किसी टैक्स वगैरह का सवाल नहीं था। सवाल इसका था कि टाल वगैरह बढ़ाया जाय या नहीं, और वह भी खाली अखबारों में आया है।

श्री रघुनाथ सिंह: आपने कुछ फैसिलिटीज की बात कही है। मैं यह जानना चा ता हूं कि रिवर नेवीगेशन के वास्ते पाकिस्तान की ओर से हमें कितनी फैसिलिटीज प्राप्त होगी और आप क्या फैसिलिटी उनको देंगे ?

श्री राज बहादुर : तीन तरह की फैसिलिटीज होती हैं रिवर नेवीगशन में, एक पाइलटिंग दूसरी कंजर्वेंसी और तीसरी लाइट्स जो कि दोनों किनारों पर लगाई जाती हैं, निशान लगाये जाते हैं। तीनों तरह की फैसिलिटीज ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस साइड के कस्टमर्स को और उसके लिये कस्टमर्स को टाल देना पड़ता है।

Shri D. C. Sharma: What is the total value of the inter-State trade which passes through the rivers of Pakistan?

Shri Raj Bahadur: I cannot exactly give the value, but it is a fact that about 60 per cent of our goods are carried from Assam to Bengal and from Bengal to Assam by the river services.

Shri Kapur Singh: May I know whether there are any indications available of any Pakistani intentions to make such commerce uneconomical for India; if so, what do the Government propose to do about it?

Shri Raj Bahadur: No such signs are there. As a matter of fact, even the press reports have clearly indicated that there is no suggestion of any discrimination in regard to the imposition of these tolls and levies between their own steamers and the steamers of foreign countries, namely, India.

Shri P. C. Borooah: Since when is the Government transport company functioning and what is the strength of its fleet plying on the route?

Shri Raj Bahadur: It is an old service. I cannot exactly give the date.

चावल का रक्षित भंडार

\+

*३०२ { श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सरजू पांडेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बीस लाख टन चावल का रक्षित भंडार बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से तथा किन मूल्यों पर चावल खरीदा जायेगा ; और

(ग) चावल की पैदावार बढ़ाने के लिये भारतीय किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चावल का रक्षित भंडार कुछ देशों से आयात कर और कुछ देश के भीतर खरीद कर बनाए जाने का विचार है । आगामी कुछ वर्षों में चावल संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से, जहां भाव अनकूल हों और चावल की किस्म भी स्वीकार्य हों, आयात किये जाने की सम्भावना है । जिन भावों पर चावल वास्तव में आयात किया जाएगा व खरीद का ठेका करते समय निश्चित करने पड़ेंगे । देश के भीतर खरीदारी प्राप्ति भावों पर जो समय समय पर विभिन्न किस्म के चावलों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, की जाएगी ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण जिसमें चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, बताया गया है, रखा जाता है ।

विवरण

(१) कृषि सम्बन्धी औजारों और फास्फोरस उर्वरकों पर पहले से ही उपदान सुलभ हैं । हाल ही में, केल्शियम एम्मोनियम नाइट्रेट के भाव भी कम कर दिए गए हैं । चावल की सघन खेती कार्यक्रम द्वारा जितने क्षेत्र में खेती की जाती है वहां पौधा संरक्षण उपायों के लिये दिया जाने वाला उपदान २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है ।

(२) राज्य सरकारों से कहा गया है कि चावल की खेती सम्बन्धी आवश्यक औजारों को खरीदने के लिए पंचायतों और किसानों को २५ प्रतिशत उपदान देवें ।

(३) जिन क्षत्रों में सरकारी खरीदारी नहीं हो रही है वहां चावल के न्यूनतम आधार भाव निर्धारित कर दिए गए हैं । जिन क्षेत्रों में सरकारी खरीदारी हो रही है वहां प्राप्ति भाव निर्धारित कर दिए गए हैं जो कि आधार भावों का कार्य करते हैं । इन भावों पर चावल की खरीदारी होने से खेतीहरों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है ।

[(a) Yes, Sir.

(b) The buffer stock is proposed to be built partly out of imports and partly from internal procurement. In the next few years, rice is likely to be imported from U.S.A., U.A.R., Burma and other South East Asian countries where prices may be favourable and the quality acceptable. The prices at which rice will be actually imported will have to be negotiated at the time the purchase contract is entered into. Internal procurement will be made at the procurement prices for different varieties of rice fixed from time to time.

(c) A statement showing the incentives being given to Indian farmers for increasing the production of rice is laid on the table of the Sabha.

STATEMENT

(1) Subsidies are already available on agricultural implements and phosphatic fertilizers. Prices of Calcium Ammonium Nitrate has also recently been reduced. The subsidy for plant protection measures has been increased from 25 per cent to 50 per cent for areas coverd by the intensive rice cultivation programme;

(2) The State Governments have been asked to grant a subsidy of 25 per cent to Panchayats and individual cultivators for purchase of necessary implements for rice cultivation;

(3) Minimum support prices for rice have been fixed in areas where Government procurement is not in operation. In areas where Government procurement is in operation, procurement prices have been fixed which act as support prices. Purchases of rice at these prices ensure a reasonable return to the cultivator for his produce.]

श्री यशपाल सिंह : जैसा कल ही इस आदरणीय सदन में माननीय मनुभाई शाह ने बतलाया, हम बासमती दूसरे देशों को भेज र हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि जब हमारे यहां चावल की कमी है और हमें दूसरे देशों से चावल लेना पड़ता है तो इस देश में होने वाले बासमती चावल को कैसे दूसरे स्थानों को भजा जा रहा है ? यानी दूसरे देशों को हम बढ़िया चावल भेज रहे हैं ?

Shri A. M. Thomas: So far we have exported only 5000 tons of basamati rice.

श्री यशपाल सिंह : हमारे माननीय खाद्य मंत्री अभी जापान तशरीफ ले गये थे । क्या मैं जान सकता हूं कि जापान के तरह के य ां पर कितने एग्रिकल्चर फार्म हैं, यानी ऐसे फार्म जिनमें जापानी ढंग का चावल पैदा किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी चार हैं और आगे और ज्यादा होने की उम्मीद है ।

श्री बड़े : क्या यह बात सत्य है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ एरिया में प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी काश्तकार से जो चावल लिया जाता है सरकार के द्वारा उसकी ऐक्चुअल प्राइस में और मार्केट की प्राइस में इस समय बड़ा अन्तर है और इसलिये राइस ग्रोइंग काश्त-कार जो हैं उन्होंने राइस बोना बन्द कर दिया है ?

Shri A. M. Thomas: It is true that there is a lot of difference between the procurement price and the open market price. But we are having only about 25 per cent levy so that as far as 75 per cent is concerned, it is sold at the market rate. This year, in Madhya Pradesh the production was much below expectation---there was a drop to the extent of a million tons.

श्री प्रिय गुप्त : जसा माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, अभी फूड प्रोडक्शन के सम्बन्ध में कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट होने में बहुत वक्त लगेगा और इसलिए बफर स्टाक रखा जायेगा । तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस चावल को रखने के लिये कितने फ्लोर एरिया की जरूरत होगी ? इस में से कितना परसेंटेज वेयरहाउसिंग सरकार की तरफ से किया गया है और कितने अनसर्विसेबल गोडाउन्स हैं ज ां यह गल्ला खराब हो जाता है जिस के कारण सरकार को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है । इसके लिये सरकार का क्या प्रपोजल है ?

Shri A. M. Thomas: In early 1960 we wanted to build up a buffer stock of 5 million tons—4 million tons of wheat and 1 million tons of rice. Recently we have raised that target and now it is 4 million tons of wheat and 2 million tons of rice. With regard to the storage space available, the position, was not quite satisfactory a few years back. Now the position is satisfactory. We have got our own storages constructed to the extent of 2 million tons and we have hired accommodation to the extent of 1 million tons so that there will not be any difficulty with regard to storage when we are in a position to build up a buffer stock.

Shri S. M. Banerjee: From the statement of the hon .Minister, it appears that partly from the imported rice and partly from our country's rice this buffer stock will be built. I want to know whether this will not be done at the cost of our internal

consumption and the quotas released to various State Governments.

Shri A. M. Thomas: The internal procurement will depend upon the internal production. For example, this year, with all our efforts, we were in a position to procure only about 6 to 7 lakh tons because of the shortage of production even in surplus areas of Madhya Pradesh and also in Punjab. In fact, we had tried to procure a much large quantity, but that was not possible. So, if we are to only procure internally there is a limit about the quantity that can be procured. We have to import from foreign countries also and that will depend upon. . . .

Mr. Speaker: The question only was whether this will not affect our internal consumption.

Shri S. K. Patil: There is evidently a mistake. What is procured for the internal consumption is not a buffer stock. The hon. Members sometimes confuse buffer stock with what we regularly need. Buffer stock is something over and above that and, therefore, that position can only come when we are surplus in rice.

Shri S. M. Banerjee: My question has not been understood properly. I am clarify it. I am not confused at all. I only want to know whether the hon. Minister will give us an assurance that the internal procurement for building up the buffer stock will not be done at the cost of internal consumption.

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): Surely, nothing will be taken unless it is really a buffer stock.

Shri Nath Pai: Is it true that this policy of building buffer stocks is likely to be scrapped in view of the impending change in the Ministry, this policy being associated with the present holder of that office?

Shri S. K. Patil: In the new circumstances also, people will like to eat rice.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether Government are aware that there is a great unrest amongst the farmers of Madhya Pradesh that the difference between the prevailing prices and the procurement prices is too much, and if so, what action Government are taking in this matter?

Mr. Speaker: I suppose that that has been answered.

Shrimati Savitri Nigam: My question is entirely different....

Mr. Speaker: That question has been substantially answered.

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो विदेशों से चावल खरीदा है उसकी हिन्दुस्तान पहुंचने पर क्या कीमत पड़ेगी ?

Shri A. M. Thomas: With regard to Burma rice, the landed cost is somewhere about Rs. 20.

Shri P. Venkatasubbaiah: In the statement that has been laid on the Table of the House, it has been stated that certain incentives have been given to the farmers. May I know whether in spite of that, owing to the inadequacy of the incentives, there has been a general decrease in rice production in the country, and the agriculturists are switching over to commercial crops, and if so, whether Government propose to give more incentives?

Shri A. M. Thomas: In fact, these incentives are intended to keep a balance between the cash crops and the foodgrains crops. We need not be anxious at all about the diversion to cash crops, because they earn much-needed foreign exchange, and the area that is now utilised for cash crops is not unduly large also.